

**Micro-project for development of tribals
in Orissa**

727. SHRI RAHASBIHARI BARIK:
Will the Minister of SOCIAL JUSTICE
AND EMPOWERMENT be pleased to
state:

(a) the Micro-projects for development
of Tribals in Orissa as on date;

(b) the funds allocated by Government
to NGOs, District-wise, and

(c) the details of the activities undertaken
by these NGOs in the State, so far,
and the number of persons benefited
during each of the last three years?

**THE MINISTER OF STATE OF THE
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE
AND EMPOWERMENT (SHRIMATI
MANEKA GANDHI):** (a) Seventeen
micro projects are functioning for welfare
and development of Primitive Tribal
Groups in Orissa.

(b) and (c) Under the Central Sector
Scheme of grant in aid to NGOs,
Rs.79.04 lakhs, Rs. 149.41 lakhs and
Rs.9551 lakhs were provided to different
NGOs in the State of Orissa during the
years 1995-96, 1996-97 and 1997-98
respectively for the welfare and develop-
ment of Scheduled Tribes. With these
grant in aids various activities such as
residential schools, orphanages, library,
hostels, balwadies, creches, medical units,
computer training, shorthand and typing
training, kanyashram etc were undertaken
to benefit about 23,000 tribals annu-
ally for each year of last three years.
These grant in aids are not given to
NGOs district wise.

जनजातीय क्षेत्र कल्याण निधि

728. श्री चीमनभाई हरी भाई शुक्ला: क्या
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने
की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय क्षेत्र कल्याण निधि (जनजातीय
उपयोजना) के लिए धनराशि में भारी कमी/गिरावट आई
है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को गुजरात से कुछ
कल्याण योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है
और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा गुजरात में कल्याण योजनाओं के
कार्यान्वयन के द्वारा बेसहारा बच्चों के रहन-सहन के स्तर
को ऊंचा उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की
राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी):** (क) जी, नहीं।
आदिवासी उप योजना प्रवाह वर्ष 1996-97 की तुलना
में वर्ष 1997-98 के दौरान पूर्ण अर्थ तथा राज्य योजना
के प्रति प्रतिशतता दोनों के लिए उच्चतर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और
सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा
बेसहारा बच्चों, खास कर वे जो बेघर तथा बिना
पारिवारिक बंधनों के हैं, के बच्चों के स्वास्थ्य विकास के
लिए आवश्यक गैर संस्थागत समर्थन प्रदान करने के
उद्देश्य से बेसहारा बच्चों के लिए एक समर्पित
कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना
के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों,
स्थानीय निकायों, सहकारी समितियां, शैक्षिक तथा अन्य
संस्थाओं और अन्य गैर सरकारी संगठनों आदि को
वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1998-99 के दौरान,
गुजरात में अब तक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए
10 गैर सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की गई है
तथा 31.68 लाख रु० की धनराशि उन्हें निरुक्त की गई
है।

**Schemes for upliftment of SCs, STs and
minorities**

729. SHRIMATI BASANTI SARMA:
Will the Minister of SOCIAL JUSTICE
AND EMPOWERMENT be pleased to
state:

(a) the details of Welfare Schemes/
programmes being formulated and im-
plemented in the country by Government
for the upliftment of SC, ST and
minorities Communities;